चीनी पर आयात शुल्क वृद्धि से साफ इनकार

सरकार ने कहा- मौजूदा हालात में आयात शुल्क बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं

प्रेट्र • नई दिल्ली

सरकार ने आज साफतौर पर कहा है कि चीनी के आयात पर शुल्क नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि चीनी मिलें आयात नियंत्रित करने के लिए शुल्क बढ़ाने की लगातार मांग कर रही हैं।

वित्त राज्य मंत्री एस. एस. पलानीमाणिक्कम ने लोकसभा में बताया कि उद्योग संगठनों और चीनी मिलों से ज्ञापनों का गंभीरता से अध्ययन किया गया और जरूरी कारकों जैसे अंतरराष्ट्रीय मूल्य, घरेलू मूल्य, आयात हो रही मात्रा और घरेलू उत्पादन पर विचार किया गया। इसके बाद निर्णय किया गया है कि चीनी के आयात पर शुल्क बढ़ाना न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यकता है। लोकसभा में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार को आयातित चीनी की सप्लाई सीमित करने के मकसद से 60 फीसदी आयात शुल्क लगाने की मांग प्राप्त हुई है। इस सवाल पर मंत्री ने उक्त जवाब दिया। ब्राजील के बाद दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में चाल सीजन 2012-13 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान चीनी का उत्पादन घटकर 243 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले साल देश में चीनी का उत्पादन 260 लाख टन रहा था। देश में करीब 220 लाख टन चीनी की सालाना खपत रहती है।

चीनी उद्योग संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि घरेलू बाजार में आयातित चीनी पर अंकुश लगाने के लिए उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाए। विश्व बाजार में चीनी के दाम कम होने के कारण कई मिलें रॉ शुगर आयात कर रही हैं और उसकी रिफाइनिंग करके तैयार चीनी (व्हाइट शुगर) की घरेलू बाजार में सप्लाई कर रही हैं। इस वजह से घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों पर दबाव बन रहा है। इससे चीनी मिलों को कम भाव पर बिक्री करनी पड रही है।